

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

31.07.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1513 का उत्तर

कोटिपल्ली-नरसापुर रेल लाइन का निर्माण कार्य

1513. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने कोटिपल्ली-नरसापुर रेल लाइन के निर्माण कार्य पर कोई शोध/सर्वेक्षण/अध्ययन कराया है;
- (ख) यदि हां, तो इस रेल लाइन के निर्माण के लिए राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा जारी निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) उक्त परियोजना की वर्ष-वार प्रगति का ब्यौरा क्या है तथा परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और
- (घ) उक्त परियोजना में विलंब के कारणों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

कोटिपल्ली-नरसापुर रेल लाइन का निर्माण कार्य के संबंध में दिनांक 31.07.2024 को लोक सभा में श्री जी. एम. हरीश बालयोगी के अतारांकित प्रश्न सं. 1513 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): कोटिपल्ली-नरसापुर (57.21 किमी) नई लाइन परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया था, जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार को परियोजना की 25% लागत प्रदान करनी है। परियोजना की स्वीकृत लागत 2120 करोड़ रुपए है और मार्च 2024 तक 1181.19 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इस परियोजना में मार्च, 2024 तक लगभग 416.79 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता में से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा केवल लगभग 163.02 हेक्टेयर भूमि ही सौंपी गई है। उपलब्ध भूमि में कार्य प्रगति पर है। गौतमी, वशिष्ठ और वैनतेय नदियों पर महत्वपूर्ण पुलों का कार्य शुरू हो चुका है। 2024-25 के लिए 125 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

2014 से, भारतीय रेल में परियोजनाओं के लिए निधि आटन और तदनुरूपी कमीशनिंग में काफी वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः स्थित अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए वार्षिक बजट आबंटन इस प्रकार है:

वर्ष	बजट परिव्यय	2009-14 के औसत आबंटन की तुलना में वृद्धि
2009-2014	886 करोड़ रुपए/वर्ष	-
2023-2024	8,406 करोड़ रुपए	9 गुना से अधिक
2024-25	9151 करोड़ रुपए	10 गुना से अधिक

आंध्र प्रदेश राज्य में पूर्णतः/अंशतः स्थित अवसंरचना परियोजनाओं को कमीशन करने की स्थिति इस प्रकार है:

अवधि	कमीशन की गई कुल लंबाई	कमीशन की गई औसत लंबाई	2009-14 के दौरान औसत कमीशनिंग की तुलना में परिवर्तन
2009-14	363 किमी	72.6 कि.मी./वर्ष	-
2014-24	1,510 किमी	151 कि.मी./वर्ष	2 गुना से अधिक

रेल परियोजना(ओं) का पूरा होना/निष्पादन होना राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृति, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृति, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थिति, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु की परिस्थितियों के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और यह सभी कारक परियोजना(ओं) के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

\*\*\*\*\*